1984 to 1986, only four samples of wheat seed have been found to contain the excessive residue of the pesticide used. Instructions were accordingly issued to the millers/dealers and National Seeds Corporation by the Directorate General of Health Services not to use such seeds for human consumption.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आर०एल०ई०जी०पी० के अधीन उत्तर प्रदेश में कुंओं का निर्माण

928. **श्री सोहन लाल धूसिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये 1988-89 में 80,000 कुंएं बनवायेगी और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कितना प्रतिशत योगदान होगा ; और

(ख) क्या उक्त योगदान की देख-भाल स्वयं केन्द्रीय सरकार के स्तर पर की जायेगी या सब की देख-भाल उत्तर प्रदेश सरकार करेगी ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1988–89 के दौरान 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल 2395 खोदे गए कुएं बनाने का प्रस्ताव है । इन कुंओं में से आधे कुओं का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा शेष आधे कुंओं का निर्माण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी के अंतर्गत किया जायेगा । इन कुओं के निर्माण पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को किए गए आवंटनों में से किया जायेगा । क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 50 प्रतिशत नकद व्यय राज्यों द्वारा किया जाता है । केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई किए खाद्यान्नों के मूल्य सहित केवल 50 प्रतिशत नकद खर्च वहन करेगा । ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा ।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों की निगरानी का उत्तरदायित्व मूल रूप से राज्यों का है । केन्द्र सरकार भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के अतिरिक्त निर्धारित रिपोर्टों/विवरणियों और क्षेत्र अधिकारियों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी करती है ।

Child workers in India

929. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Ministerr of LABOUR be pleased to state:

(a) the total number of child workers in the country in the year 1981, and the number of these workers in the year 1987-88 as per Government estimate;

(b) whether the number of minor workers has been increasing not only in rural areas but in some factories and plantations also; and

(c) if so, what new steps Government propose to take to curb child exploitation in the country?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) and (b) According to the 1981 census based on 5 per cent sample data, the number of Child Workers in the country (excluding the State of Assam) upto the age of 14 years was 3.6 million. However, according to the projections of the National Sample Survey (NSS) conducted by National Sample Survey Organisation (NSSO) there were 16.663 million working children in the age group 5-14 years in 1977-78 and 16.668 millions in 1986. It is, not possible to say whether there has been any increase or decrease in the number of child workers in the country in recent years, because the last